माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राज्य के 17 लाख युवाओं का पंजीयन- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म के तहत प्रदेश में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की

जयपुर, 2 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए। "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" देश की इसी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का सशक्त माध्यम बन रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में 17 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को अवसर देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये नशा-मुक्ति की दिशा में भी गतिविधियाँ संचालित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशा मुक्ति, फिटनेस और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' के विज़न को हर गांव और शहर तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पेपरलीक और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ। अब भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है।

बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" युवाओं को सरकार से सीधे जोड़ने का सशक्त डिजिटल माध्यम है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएं, नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंडटेबल और माय भारत बजट क्वेस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से युवा अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, जिससे विकसित भारत के विजन को गति मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बने विकसित भारत यंग लीडर्स से संवाद भी किया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण एवं यंग लीडर्स उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा की।

- **केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण में बताया कि भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउन्ड टेबल और माय भारत बजट क्वैस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन व कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर आयोजित होते हैं।**

30 जून तक पैट्रोकेमिकल उत्पादों से कस्टम ड्यूटी हटाई

पश्चिम एशिया में जारी जंग के मद्देनज़र सरकार ने बड़ी राहत दी

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच, पेट्रोकेमिकल उत्पादों का मुख्य रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने 40 प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों से अगले तीन महीने तक के लिए पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य कच्चे माल की कीमत में होने वाली बेतहाशा वृद्धि से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुरक्षित रखना है।

अमेरिका-इज़रायल तथा ईरान के बीच जारी जंग के दौरान केन्द्रसरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से फार्मास्यूटिकल, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे उद्योगों को काफी फायदा होगा। कस्टम ड्यूटी हटाने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत में गिरावट आएगी और आम आदमी को महंगाई के बोझ से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी।

इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में एसिटिक एसिड, एपॉक्सी रेजिन, प्यूरीफाइड टैरेफ्थैलिक एसिड, मेथेनॉल, फिनोल, टॉल्यून, एनहाइड्रस अमोनिया, एथिलीन पॉलीमर्स और कई तरह के फॉर्मेल्डिहाइड पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 30 जून तक के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

- **इन उत्पादों में एसिटिक एसिड, एपॉक्सी रेजिन, मेथेनॉल, अमोनिया, एथिलिन पॉलिमर्स आदि शामिल है।**

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने इन अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इंपोर्ट से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब पश्चिमी एशिया में जियो-पॉलिटिकल टेंशन चरम पर पहुंचा हुआ है। इस टेंशन का असर दुनिया भर में अहम पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की उपलब्धता पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका और इज़रायल तथा ईरान के बीच चल रही लड़ाई के चलते वैश्विक सप्लाई चेन को भी झटका लगा है, जिसकी वजह से इन उत्पादों की कीमत में भी तेजी आने लगी है। ऐसे में कस्टम ड्यूटी हटा कर केन्द्र सरकार भारतीय उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना चाहती है।

इस संबंध में बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी में इस छूट का उद्देश्य सप्लाई को बनाए रखने और वैल्यू चेन में कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है। इस कदम से केन्द्र सरकार को यह उम्मीद भी है कि एंड कंज्यूमर्स के लिए कीमतों में स्थिरता आएगी, क्योंकि कच्चे माल की लागत में कमी से कंपनियों को उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई कीमतें का दबाव नहीं डालना पड़ेगा।

आईपैक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

काम देख रही है। आईपैक से पहले प्रशांत किशोर भी जुड़े रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार संभाल रही आई पैक नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के ऑफिस में छापेमारी की। बेंगलुरु में आईपैक के डायरेक्ट ऋषिकांत सिंह के आवास पर भी रेड हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक, कोयला तस्करी मामले की जांच के लिए आई पैक के ठिकानों को खंगाला गया है।

अदालती आदेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोग अपने आप ही चुनाव के कार्यक्रम को 15 तारीख से आगे बढ़ाने का फैसला कैसे ले सकता है, जबकि इस संदर्भ में न तो अदालत में कोई आवेदन पेश किया गया है और न ही अदालत ने कोई अनुमति दी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाअधिवक्ता को भी अदालत में उपस्थित होने का आग्रह किया। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार कुछ ही दिनों में चुनाव के कार्यक्रम को 15 अप्रैल से आगे बढ़ाने के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत करने जा रही थी। परंतु आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम कैसे और किस प्रकार से तय किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में अदालत के समक्ष ऐसा कोई भी आवेदन पेश नहीं किया गया है। अदालत ने आगे कहा कि प्रदेश के चुनाव आयोग को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव स्वतः ही आगे कैसे बढ़ाया, जबकि अदालती आदेश इसके बिल्कुल विपरीत थे। इसके साथ ही, अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करा है।

आईआरजीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के दौरान हुई। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिगेडियर जनरल फतह अलीजादेह की जान दुश्मनों के हवाई हमले में गई है।

मोहम्मद अली फतह अलीजादेह कोई साधारण फौजी नहीं थे। वे आईआरजीसी की उस स्पेशल वॉलंटियर यूनिट की कमान संभाल रहे थे, जो गुरिल्ला युद्ध और बेहद कठिन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। इस यूनिट को सीधे तौर पर फतेहिन कहा जाता है।

सीरिया के गृहयुद्ध में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार को बचाने और आतंकियों से लोहा लेने के लिए इसी फतेहिन यूनिट को मैदान में उतारा गया था।

फतह अलीजादेह जैसे अनुभवी कमांडर का मारा जाना ईरानी के लिए बड़ा क्षित है।

मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ब्रिज पर अमेरिका का हमला

तेहरान, 02 अप्रैल। ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाले एक 'बी1 हाईवे ब्रिज' पर गुरुवार को हवाई हमला किया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और आसपास के इलाकों में भी नुकसान हुआ है।

यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचे पिलर वाला यह प्रोजेक्ट करीब 400 मिलियन डॉलर में बना था।

- **3800 करोड़ रु. की लागत से बना यह पुल तेहरान को ईरान के उत्तरी भाग से जोड़ता है।**

इसका मकसद तेहरान को उत्तरी इलाकों से जोड़ना और व्यापार को आसान बनाना था। रिपोर्ट के मुताबिक कराज के अजीमियेह इलाके और कराज नॉर्दर्न बायपास पर इस पुल को निशाना बनाया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया है।

यह पुल ईरान बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, इसलिए इसके नुकसान से ट्रैफिक और व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है।

पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने भारत की कूटनीति को सराहा

इससे पहले शशि थरुर भी भारतीय नीति की सराहना कर चुके हैं

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। शशि थरूर के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया के ताजा संकट में भारत की कूटनीति को परिपक्व और कुशल बताते हुए कहा है कि इसने संभावित खतरों से सफलतापूर्वक बचाव किया है।

इस कूटनीतिक पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आम सहमति और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। शर्मा का यह बयान अमेरिका-इज़रायल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रूख से अलग है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस इस युद्ध के दौरान भारत की कोई कूटनीतिक भूमिका नहीं होने से लेकर, एलपीजी रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल की कमी होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की आलोचना करते रहे हैं। रोचक तथ्य यह है कि पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता कमलनाथ ने भी एलपीजी की किल्लत को केवल अटकल बताया और कहा कि कोई कमी नहीं है। गुरुवार को आनंद शर्मा ने एक बयान में कहा कि ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के अनुचित हमले के बाद दुनिया भर में उथल-पुथल मच गई है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है।

- **इसके विपरीत कांग्रेस नेतृत्व लगातार भारतीय कूटनीति का विरोध कर रहा है।**
- **एक अन्य नेता कमलनाथ ने भी कहा कि एलपीजी संकट नहीं है।**

शर्मा ने कहा कि भारत के खाड़ी देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं और ईरान से सभ्यतागत रिश्ते हैं। पेट्रोलियम, एलपीजी और पीएनजी जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तियों और 200 अरब डॉलर के व्यापार के अलावा, एक करोड़ से ज्यादा भारतीय प्रवासियों के हितों की सुरक्षा के साथ लगभग 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के आने के साधन का भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस संकट से निपटने में भारत की कूटनीति काफी परिपक्व और कुशल रही है, जिसने संभावित खतरों से सफलतापूर्वक बचाव किया है।

अपने बयान को सही ठहराते हुए बातचीत में कहा कि उन्होंने सरकार के संदर्भ में नहीं, भारत की कूटनीति की कुशलता की बात की है, जिसमें हमारे राजनयिकों की बड़ी भूमिका है। पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की सरकार की पहल को सही ठहराते हुए शर्मा ने कहा कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आम सहमति और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए।

होर्मुज़ स्ट्रेट पर ब्रिटेन में 60 देशों की मीटिंग

भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहल पर करीब 60 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑनलाइन तरीके से होर्मुज़ संकट पर गुरुवार को चर्चा की। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कूपर ने की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था।

मिसरी ने वर्चुअल माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया।

- **भारत ने मीटिंग में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत इकलौता देश है जिसने अपने जांबाज़ नाविकों को खोया है।**

उन्होंने दुनियाभर के देशों के सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही हर देश का हक है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश सचिव ने चिंता जताई कि इस पूरे संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है।

ब्रिटेन की ओर से बुलाई गई बैठक में भारत ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने अपने जांबाज नाविकों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल और अधिक युद्ध नहीं है। अगर दुनिया को इस संकट से बाहर निकलना है, तो सभी पक्षों को तुरंत हथियारों को शांत कर बातचीत की मेज पर लौटना होगा।

वहीं, बैठक के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, होर्मुज़ से जहाजरानी सेवाओं को फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा और इसके लिए समुद्री उद्योग साझेदारी के अलावा, सैन्य शक्ति और राजनयिक गतिविधियों का एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक होगा। स्टार्मर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उस अपील को स्पष्ट नकार चुके हैं कि ब्रिटेन व यूरोप के अन्य देशों को होर्मुज़ खुलवाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहिए।

इस बीच, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी दी कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से आवागमन का मुद्दा ईरान युद्ध का ही परिणाम है और जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जलडमरूमध्य स्थिर नहीं रहेगा। वांग यी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने शीघ्र युद्धविराम का भी आ ान किया।

ऑस्ट्रिया ने भी अमेरिका को एयरस्पेस देने से इन्कार किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ईरान और यूएस -इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, कई देश युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे समय में अमेरिका को झटका लगा है। अब ऑस्ट्रिया ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है।

ऑस्ट्रिया ने ईरान से जुड़े सैन्य ऑपरेशनों के लिए अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की अमेरिकी मांग ठुकरा दी है। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला देश के सख्त तटस्थता कानून के तहत लिया गया है।

ट्रंप ने अमेरिकी जनता से कहा, हम जीत गए हैं

अमेरिका की जनता को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान को नष्ट करने का दावा किया

वॉशिंगटन, 02 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध पर देश को संबोधित किया है। भारतीय समयानुसार, गुरुवार सुबह साढ़े छह बजे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान सफल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज ने बहुत कामयाबी के साथ ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म करते हुए उनकी परमाणु हथियार हासिल करने की उम्मीद को खत्म किया है। उन्होंने ईरान में अमेरिका के लक्ष्य पूरे होने का ऐलान किया है।

- **ट्रंप ने कहा कि ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है।**

राष्ट्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है। यह एक ऐसी जीत है, जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है। उनकी हथियारों की फैक्टरियां तथा रॉकेट लॉन्चर टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे रह गए हैं।

सात जजों को नौ घंटे बंधक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के एक समूह ने न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जो एसआईआर से संबंधित जरूरी कार्य कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हर चीज "राजनीतिक" हो चुकी है, जिसके कारण प्रशासन पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। सवाल यह है कि राज्य में बढ़ती अराजकता और हमलों के बावजूद केन्द्र सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है।

निकृष्ट किस्म की हिंसा की इन घटनाओं के बावजूद, आरोप है कि ममता बनर्जी खुले मंचों से और उकसाने वाले बयान दे रही हैं। उन्होंने कांग्रेस, ओवैसी, माकपा तथा भाजपा पर इन घटनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है।

बताया गया कि उन्होंने लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, से अपील की कि जो भी उनके पास उपलब्ध हो, उसके साथ बाहर निकलें और एसआईआर कार्य को रोकें। उन्होंने यह भी कहा कि "हमारी माताएं और बहनें चुप क्यों हैं?" और वादा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम नहीं होने दिया जाएगा।

ममता बनर्जी हर कदम पर गैर-जिम्मेदारी और उकसावे की राजनीति को बढ़ाती रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर वे नहीं होतीं, तो बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) जीवित नहीं रहता। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनके बिना, यह समुदाय दूसरे समुदाय के हमलों का शिकार हो सकता है।

इसके बाद से वे किसी भी कीमत पर एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) कार्य को रोकने के लिए संगठित प्रयास करती नज़र आई हैं। राज्य के शीर्ष राजनीतिक स्तर से दिए गए ऐसे बयानों के बाद लोगों में टकराव का माहौल बन गया है।

चार न्यायिक अधिकारी एसआईआर के तहत मतदाता सूची सुधार का काम कर रहे थे। इन अधिकारियों को भीड़ ने उनके कार्यालय में घेरकर रोक लिया, जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के आ ान के अनुरूप ही हुआ।

इन न्यायिक अधिकारियों ने पहले ही राज्य प्रशासन और कलकत्ता उच्च न्यायालय को उस क्षेत्र में अपनी असुरक्षा के बारे में सूचित किया था, जहां वे कार्य कर रहे थे।

उन्होंने अपने कार्यस्थल को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उनकी मांग को राज्य प्रशासन तक ठीक से पहुंचाया ही नहीं गया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं राज्य प्रशासन को सुरक्षा देने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि न्यायिक अधिकारियों को ही सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं।

पूरा कार्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किया जा रहा है।

आप ने राघव चड्ढा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकसभा के 128 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, तब पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा ने कथित तौर पर उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

सूत्रों का कहना है कि कई मौकों पर चड्ढा सदन में बने रहे, जबकि आप सहित, विपक्ष के अन्य सदस्य वॉकआउट कर गए थे।

वर्ष 2025 के दिल्ली चुनावों में आप की हार के बाद चड्ढा ने पार्टी के भीतर तो लो प्रोफाइल रखा और केवल व्यापक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित रखा था।

बताया जाता है कि चड्ढा ने आप संस्थापक अरविन्द केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित शराब घोटाले में बरी होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाल ही में केजरीवाल द्वारा भाजपा के खिलाफ संबोधित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा में भी वे अनुपस्थित रहे। एक सूत्र ने कहा, "वे अपना अलग एजेंडा चला रहे थे।"

हाल ही में चड्ढा ने भारत में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठाकर सुर्खियां बटोरी थीं। उनका कहना था कि बच्चे के जन्म पर माता-पिता, दोनों को बधाई दी जाती है, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी मुख्यतः मा ता पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि पालन-पोषण की जिम्मेदारियां समान रूप से साझा होनी चाहिए और यह चीज कानूनों में भी प्रतिबिम्बित होनी चाहिये।

हवाई अड्डों पर महंगे खाने के खिलाफ उनकी पहल के चलते 'उड़ान यात्री कैफे' जैसे किफायती फूड काउंटर शुरू किए गए, जिससे यात्रियों को सस्ता खाना मिल सके। इसे उपभोक्ता अधिकारों की जीत बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के इस फैसले से नाराज चड्ढा भाजपा नेतृत्व के संपर्क में हैं और उनके भगवा दल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एडवोकेट पीबी सुरेश ने दलील देते हुए कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे और उनके अधिकारों को संरक्षित रखे।

खंडपीठ ने उनकी अपीलों पर पक्षकारों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में भर्ती परीक्षा होने से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने भर्ती की सभी जरूरी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली हैं।

ऐसे में इस स्तर पर भर्ती परीक्षा स्थगित करने से अव्यवस्था पैदा होगी। इसलिए भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं की जाए।

'5037 बीघा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मकान तोड़ने की नौबत आ जायेगी।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पी सी भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार को और हाउसिंग बोर्ड को अपनी जमीन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिये और इसी में राज्य सरकार का और आम जनता का हित है। उन्होंने कहा कि 5037 बीघा जमीन में से वह जमीन, जिस पर अतिक्रमण नहीं है, उसे बचाने का प्रयास राज्य सरकार को पूरी तरह से करना चाहिये। सुनवाई के दौरान अदालत ने एडिशनल सॉलिसीटर जनरल (ए.एस.जी.) से आश्वासन लिया कि राजस्थान सरकार व हाउसिंग बोर्ड सुनिश्चित करें कि उक्त भूखंड में शेष खुले स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होने दिये जायेगा। अदालत ने आदेश दिये हैं कि हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता के वकील पूरे क्षेत्र का विस्तृत मैप बनायें, जिसमें विवादित क्षेत्र और खुले क्षेत्रों को अच्छे से अंकित किया गया हो, ताकि अतिक्रमण होने से रोका जा सके। अदालत ने इस दस्तावेज को बनाने व अदालत में पेश करने के लिये एएसजी व याचिकाकर्ता को समय दिया है और इस मामले की अगली तारीख 1 मई, 2026 तय की है।

वृद्धा से 80 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपराध है। जिसमें कई स्तरों पर करीब ढाई दर्जन से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया है।

जमानत याचिका में कहा गया था कि उसके खाते में पांच लाख रुपए आए थे और वह पीड़िता को दस लाख रुपए देकर राजीनामा कर रहा है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं अदालत में पेश होकर पीड़ित महिला ने कहा था कि उसे जांच एजेंसी न्याय नहीं दिला पा रही है और वह दबाव में राजीनामा कर रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने गत 27 मार्च को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908